

प्रेषक,

अंजली प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 03 जनवरी 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-2008 में राजकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय अगस्तमुनि
रुद्रप्रयाग में भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री वजत/915/2007-08 दिनांक 26-4-08 तथा एवं शासनादेश संख्या 917/xxiv (7)/2006 दिनांक 19-1-06 एवं शासनादेश संख्या 270/xxiv (7)/2006 दिनांक 11-3-08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय महाविद्यालय अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग के लेक्चर थियेटर एवं छात्रावास भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अनुमोदित आगणन रु0 2,20,00,000/-के विरुद्ध अवशेष धनराशि रु0 73,50,000.00 (रु0 तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र) को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं भित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत सम्बन्ध शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग तथा कार्य पूर्ण किया जाना शीघ्रता से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4- निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था का धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के निम्न-एकत्रिंशक रिक्वायरमेंट के अनुरूप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सम्मति प्राप्त कर लेंगे। यदि

लिखित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को कार्ली सूची में सम्मिलित करने एवं कार्यवाही अगल में लाई जायेगी।

5- उक्त निर्माण कार्य में आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर, जो गृह वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार प्राविधानित किया गया है, जो सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा सूच्यत अभिलेखों में तकनीकी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्यय की अनुदान सं० 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक 4202 शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -01- सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा-आयोजनागत-11-आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना -24-मूल्य निर्माण कार्य के नाम आला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 623 (p) XXXVIII(1)/2007 दिनांक 6-1-2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्माण मिले जा रहे हैं।

मन्दीय,

(अंजनी परमार)

सचिव

सं० 4222 (1)/xxiv (7) 82(2)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रित

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।

3- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

4- कोषाधिकारी हल्द्वानी-नैनीताल।

5- प्रयोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर इकाई।

6- प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरतमुनि - रुद्रप्रयाग।

7- निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।

8- बजट राजकोपीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।

9- वित्त अनु०-3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।

10- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आदेश सं.

(इन्दर नीवाडे)

अपर सचिव